दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, रविवार, 08 मई 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 219

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

हैदराबाद ऑनर किलिंग पर तेलंगाना को एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक 25 वर्षीय व्यक्ति की उसकी पत्नी के भाई और हैदराबाद में एक अन्य व्यक्ति की कथित ऑनर किलिंग में हत्या का स्वत: संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव को यह रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है कि क्या अंतरजातीय या अंतर्धार्मिक विवाह के मामलों में ऑनर किलिंग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार की कोई नीति है। डीजीपी को मामले में जांच की वर्तमान स्थिति, पीड़ित की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई किसी भी राहत की जानकारी देने के लिए कहा गया है। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा, आयोग यह भी जानना चाहेगा कि क्या इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई चूक हुई है, यदि हां, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कथित तौर पर कहा है कि लड़की का भाई उसके अंतर-धार्मिक विवाह का विरोध कर रहा था और इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। जैसा कि समाचार रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, युगल स्कूल और कॉलेज में सहपाठी थे और 5 साल से अधिक समय से प्यार में थे। जबकि लड़की का परिवार रिश्ते के खिलाफ था।

कर्नाटक के पूर्व मंत्री बने संन्यासी

बेंगलुरु (आरएनएस)। सांसारिक मामलों को अलविदा कहते हुए कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बीजे पुट्टस्वामी ने संन्यासी यानी तपस्वी जीवन शैली को अपनाया। 15 मई को, वह थाईलेश्वर गनीगरा महासंस्थान मठ के पहले पुजारी के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और पूर्णानंदपुरी स्वामी के रूप में नामित होंगे। कैलासा आश्रम महासंस्थान मठ के द्रष्टा जयेंद्र पुरी द्वारा पुट्टस्वामी को संन्यास या तप में दीक्षित किया गया था। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। 83 वर्षीय राजनेता हाल तक कर्नाटक राज्य नीति और योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। इससे पहले, उन्होंने जगदीश शेट्टार कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया था। पुट्टस्वामी को पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से नजदीकी के लिए जाना जाता था।

अनुराधा पौडवाल की मांग, लाउडस्पीकर से अजान पर लगे बैन; कहा- मुस्लिम देशों में भी है रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र और मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों की आवाज को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर बहस तेज है। इस बीच मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। हजारों सुरीले गीतों को आवाज दे चुकीं अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भारत में इस तरह से अजान दिए जाने की जरूरत नहीं है। अनुराधा पौडवाल ने कहा, मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर गई हूं। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है, जैसा कि भारत में होता है। मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत में इसे जबरन प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके चलते अन्य समुदाय यह सवाल उठाते हैं कि यदि वे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। अनुराधा पौडवाल ने कहा, मैं मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर चुकी हूं। वहां लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर बैन है। जब मुस्लिम देश भी इसे प्रोत्साहित नहीं कर रही हैं तो फिर भारत में इसकी क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि यदि यह प्रैक्टिस जारी रही तो फिर दूसरे लोग लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा चलाने लगेंगे। इससे समाज में सद्भाव समाप्त होगा, जो अच्छी बात नहीं है। अनुराधा ने कहा कि भारत में युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति के बारे में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने 4 वेदों, 18 पुराणों और 4 मठों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें इन बेसिक्स के बारे में पता होना ही चाहिए। यह पहला मौका नहीं है, जब किसी सिलेब्रिटी ने लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जाहिर की है।

उपराष्ट्रपति ने की पर्यावरण संरक्षण के लिए जन आंदोलन की अपील

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने आज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के लिए सक्षमकारी नीतियों के साथ-साथ लोगों से सामूहिक कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा 1.5 डिग्री तक की सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग की सीमा प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए, हमें वृहद स्तरीय प्रणालीगत बदलावों के साथ-साथ सूक्ष्म स्तरीय जीवनशैली विकल्पों दोनों का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है।

नायडु ने बढ़ती उग्र घटनाओं और घटती जैवविविधता की वास्तविकता को कम करने के लिए गंभीर आत्मनिरीक्षण और निर्भीक कदमों की अपील करते हुए कहा कि यह न केवल सरकार का कर्तव्य है कि वह इस पर विचार-विमर्श करे, बल्कि यह पृथ्वी पर प्रत्येक नागरिक और मनुष्य का कर्तव्य है कि इस ग्रह को बचाएं।

उपराष्ट्रपति मोहाली के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पर्यावरण विविधता और पर्यावरण न्यायशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, नायडु ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा जलवायु कार्रवाई में विश्व में अग्रणी रहा है। उन्होंने हाल ही में ग्लासगो में ष्टहक्क26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

यह उल्लेख करते हुए कि कैसे भारतीय संस्कृति ने हमेशा प्रकृति का सम्मान किया है और उसकी पूजा की है, नायडु ने कहा कि भारत ने संविधान में पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों को प्रतिष्ठापित किया है और विकसित दुनिया में पर्यावरण चर्चा को गति मिलने से पहले ही कई संबंधित कानूनों को पारित किया है। उन्होंने कहा, यह भावना हमारे प्राचीन मूल्यों से बहुत अधिक जुड़ी है जो मानव अस्तित्व को प्राकृतिक

पर्यावरण के हिस्से के रूप में देखते हैं, न कि इसका दोहन करने वाले के रूप में।

वर्षों से पर्यावरणीय न्याय को बनाए रखने के लिए भारतीय उच्च न्यायपालिका की सराहना करते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि निचली न्यायालयों को भी पारिस्थितिक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और स्थानीय आबादी और जैव विविधता के सर्वोत्तम हितों को अपने निर्णयों में शामिल करना चाहिए। उन्होंने प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और प्रदूषक को भुगतान करना चाहिए सिद्धांत को सख्ती से लागू करने की अपील की।

इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति ने कानूनों के ईमानदार कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया, और सुझाव दिया कि केवल कानून पारित करना पर्याप्त नहीं है, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने पर्यावरण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और स्थानीय नागरिक निकायों को संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता और दंडात्मक शक्तियों के साथ सशक्त बनाने का सुझाव दिया। यह देखते हुए कि संविधान जल प्रबंधन, मृदा संरक्षण और वानिकी के मामलों में ग्राम पंचायतों को अधिकार देता है, उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बेहतर धन आवंटन का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की और भविष्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए जमीनी स्तर के निकायों का प्रभावी कामकाज महत्वपूर्ण है।

नायडु ने स्मरण किया कि पहले के समय में गांवों के लोग साथ-साथ लगे जंगलों की रक्षा और तालाबों और नहरों की मरम्मत के लिए एकजुट होकर काम करते थे। उन्होंने जोर देकर कहा आज हमें जिस चीज की जरूरत है, वह है लोगों की मानसिकता में बदलाव। जब तक पर्यावरण संरक्षण एक जन आंदोलन नहीं बन जाता, हमारा भविष्य अंधकारमय है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के योगदान को रेखांकित करते हुए, नायडु ने कहा कि पर्यावरणीय मुकदमेबाजी की बढ़ती मांग के साथ, पर्यावरण कानून में अधिक कानूनी विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस संबंध में उपराष्ट्रपति ने गरीब वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और पर्यावरण न्याय को जरूरतमंदों के करीब लाने का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो देश के विभिन्न हिस्सों में अधिक विशिष्ट पर्यावरण पीठों का सृजन किया जाना चाहिए।

प्रकृति के दोहन की खतरनाक प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता पर बल देते हुए, नायडु ने कानून बनाने वालों से स्थिति का संज्ञान लेने और पारिस्थितिकी तथा अर्थव्यवस्था के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने वाले कानून बनाने की अपील की।

उपराष्ट्रपति ने यह भी सुझाव दिया कि छोटी उम्र से ही, छात्रों को उनकी जीवन शैली विकल्पों के कार्बन और पारिस्थितिक निशान के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों को अपने प्राकृतिक पर्यावरण-वनस्पतियों और जीवों की देखभाल करना सिखाना चाहिए- जितना कि वे अपने वास्तविक पर्यावरण की देखभाल करते हैं।

इस तरह के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के महत्व पर जोर देते हुए, नायडु ने कहा कि हमें विश्व स्तर पर एक-दूसरे से सीखना होगा और विश्व भर की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाना होगा। उन्होंने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की और आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन देश में पर्यावरण संरक्षण में एक नया अध्याय खोलेगा।

ओडिशा सरकार ने 493.62 करोड़ रुपये की छह निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दी

भुवनेश्वर (आरएनएस)। ओडिशा सरकार ने 493.62 करोड़ रुपये के छह निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिससे 1,317 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटी ने निवेश परियोजनाओंको मंजूरी दी।

राज्य ने 125 करोड़ रुपये के निवेश से जाजपुर जिले के कलिंग नगर में 2.50 लाख मीट्रिक टन टीएमटी रीबार और 2.50 लाख मीट्रिक टन वायर रॉड मिल स्थापित करने के लिए जटिया स्टील लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

121 करोड़ रुपये के निवेश के खिलाफ सोनपुर में जेआरएस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिजली संयंत्र के साथ एक इथेनॉल संयंत्र की स्थापना के लिए एक अन्य प्रस्ताव को भी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था।

इसके अलावा, एसएनएम होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के गंजम जिले के सोमोलो द्वीप में 80.25 करोड़ रुपये की लागत से एक होटल और रिसॉर्ट सुविधा स्थापित करने के प्रस्ताव को भी एसएलएसडब्ल्यूसीए द्वारा अनुमोदित किया गया था।

मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को सोलोमो जैसे संभावित द्वीपों सहित चिल्का झील में पर्यटन विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए।

यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन से टकराई कार, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

मथुरा (आरएनएस)। मथुरा के थाना नौहझील क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर हरदोई से नोएडा जाते समय वैगनआर कार अज्ञात वाहन से टकरा गई। हादसे में वैगनआर कार सवार बालक समेत 7 लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के भेज दिया है, वहीं घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया है।

जानकारी के अनुसार गांव बहादुरपुर, संडीला हरदोई निवासी लल्लू परिवार सहित नोएडा से अपने पैतृक गांव बहादुरपुर हरदोई में आयोजित शादी समारोह में भाग लेने गए थे। वहां से अपनी वैगन आर कार से नोएडा लौट रहे थे। एक्सप्रेसवे पर नौहझील क्षेत्र में माइल स्टोन 68 के समीप शनिवार तडक़े कार की अज्ञात वाहन से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसके चलते कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 9 लोगों में से एक बालक समेत 7 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक बालक और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर सभी कार सवारों को काफी मशक्कत के बाद निकाल दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया। वहीं 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए परिजनों को सूचना दी है। इस मामले में एसपी (ग्रामीण), श्रीश चंद्र ने कहा, तीन महिलाओं, तीन पुरुषों और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा और एक पुरुष अस्पताल में भर्ती हैं।

एसपी देहात श्रीश चंद्र ने बताया कि कार सवार में राजेश, लल्लू, श्रीगोपाल, संजय, निशा, छुटकी, नंदिनी के अलावा बच्चे धीरज और कृष हैं। मरने वालों में सब एक ही परिवार के हैं।

2 मंजिला इमारत में लगी आग , 7 लोग जिंदा जले

नई दिल्ली (आरएनएस)। इंदौर में तडक़े 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहां के विजय नगर की एक बिल्डिंग में पलभर में सबकुछ तबाह हो गया। दरअसल विजय नगर थाना क्षेत्र में एक तीन मंजिल वाली बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के अनुसार घटना के वक्त मकान में रहने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे थे, अधिकांश की नींद में ही जलने व दमघुटने से मौत हो गई। आग में आठ लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यह कॉलोनी इंदौर के विजय नगर इलाके में स्थित है। आग लगने की घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के साथ-साथ विजय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मृतकों के शव एमवाय अस्पताल भेजे। आग के शिकार हुए लोगों में अधिकांश किराएदार बताए गए हैं।

इंदौर के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने सात लोगों के मरने की पुष्टि की है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभवत: शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग पर काबू पाने में करीब तीन घंटे लगे।

हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से पहले आग पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी और फिर धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। इसने इतनी तेजी से विकराल रूप ले लिया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।

प्रदेश के गृह व इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। आग पर काबू पाया जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया है। फॉरेंसिक और इंटेलिजेंस के अफसर भी मौके पर मौजूद हैं। विधायक महेंद्र हार्डिया और पुलिस कमिश्नर ने भी मौके का जायजा लिया है।

शिवराज ने शोक व्यक्त किया - मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में एक मकान में आग लगने से सात लोगों के असमय निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार चौहान ने कहा कि इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान और परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करते हैं।

मालगाड़ी से कटकर हाथी की मौत, आठ घंटे प्रभावित रहा ट्रेनों का परिचालन

रांची (आरएनएस)। धनबाद-गया रेलखंड पर चिचाकी रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गयी। घटना शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात की है। इस वजह से रेलखंड पर लगभग आठ घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। माना जा रहा है कि यह हाथी झुंड से बिछड़ गया था, जो गड़ेया हॉल्ट के पास रेलवे लाइन पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया। इस घटना में गुड्स ट्रेन का एक पहिया भी क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त इस रेलखंड से किसी यात्री ट्रेन के गुजरने का शेड्यूल नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद हजारीबाग, गोमो और पारसनाथ में डाउन रेल लाइन बाधित हो गयी।

शनिवार सुबह से ही यहां लोगों की भीड़ लगी रही। घटना की सूचना के बाद रेलवे की टीम पहुंची। घटनास्थल गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। शनिवार सुबह जेसीबी की मदद से हाथी का शव हटाया जा सका। उसके बाद रेलवे ट्रैक की मरम्मत की जा सकी। लगभग 8 घंटे के बाद धनबाद-गया रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सुचारू हो सका। बता दें कि यह इलाका हाथियों का नियमित कॉरिडोर रहा है। हाथी अक्सर समूह में इधर से गुजरते हैं। कॉरिडोर से छेड़छाड़ की वजह से इस इलाके में हाथी प्राय: उत्पात भी मचाते हैं।

आकांक्षी जिलों की अवधारणा वास्तविक मानकों पर आधारित है, कार्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है

नई दिल्ली (आरएनएस)। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि आकांक्षी जिलों की अवधारणा वास्तविक मानकों पर आधारित है और महत्त्वपूर्ण समीकरणों का मूल्यांकन करके कार्यक्रम को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है।

तदनुसार, देश भर में 112 जिलों को चिह्नित किया गया है, ताकि वहां परिवर्तन लाने के लिये विशेष ध्यान दिया जा सके।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि चार वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयता प्रदान करके राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना है। डॉ. सिंह ने कल शाम को बिहार के सीतामढ़ी जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुये यह कहा। सीतामढ़ी, बिहार के 13 आकांक्षी जिलों में से एक है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एडीपी प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद के शानदार मिसाल के तौर पर उभरी है, जहां जिलों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है कि वे पहले अपने राज्य के बेहतरीन जिले के बराबर पहुंचें और उसके बाद देश के बेहतरीन जिलों में शामिल होने का प्रयास करें। इसके लिये प्रतिस्पर्धा करना और दूसरे शहरों से सीखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की बुनियादी रूपरेखा है एकरूपता (केंद्रीय और राज्य योजनाओं की), सहयोग (केंद्र, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों के बीच) और मासिक डेल्टा रैंकिंग के जरिये जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। इन सबके पीछे जन भागीदारी होगी।

एडीपी के तहत बिहार के सीतामढ़ी में किये गये कार्यों के बारे में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने संतोष व्यक्त किया कि वहां विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार आया है और शिक्षा योजना के अंतर्गत यह जिला राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल है। शिक्षा में, जिले ने पिछले चार वर्षों के दौरान 'बुनियादी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात' में 16 प्रतिशत से बढक़र 35 प्रतिशत का सुधार किया है, जो शासन तथा क्षमता निर्माण के संकेतकों में भी सुधार दर्शाता है। सीतामढ़ी स्कूल अवसंरचना के संकेतकों में भी शिखर पर पहुंच रहा है। उसने आधुनिक पुस्तकालय जैसे नवोन्मेषी उत्कृष्ट व्यवहारों में बाजी मारी है, जिले ने छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता की भागीदारी के लिये आंदोलन शुरू किया है। इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है।

सीतामढ़ी के जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार यादव ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और उन्हें अवगत कराया कि गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य तथा बाल पोषण के प्रमुख संकेतकों में कितना सुधार आया है, जिसके कारण एमएमआर व आईएमआर जैसे मुद्दों का समाधान होता है। जिले में 'संस्थागत प्रसव का प्रतिशत,' 'पूरे टीके लगे बच्चों का प्रतिशत,' 'छह वर्ष की आयु के नीचे के कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत' जैसे संकेतकों में बेहतर सुधार हुआ है। डॉ. सिंह ने सम्बंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कार्यक्रम में सर्वोच्च रैंक में पहुंचने के लिये पूरे समर्पण के साथ काम करें।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि एडीपी संकेतकों के मद्देनजर 'कृषि और जल संसाधन' में बेहतर काम किया गया है, जिसके क्रम में सीतामढ़ी को पांच परियोजनायें मिली हैं, जिनकी अनुमानित लागत 22 मार्च, 2002 के अनुसार 302.69 लाख रुपये है। इन परियोजनाओं में खुम्बी उत्पादन संयंत्र की स्थापना, खेती की मशीनरी किराये पर लेने के लिये केंद्रों की स्थापना आदि शामिल है, ताकि सीतामढ़ी में मशीनों से खेती की जा सके।

वित्तीय समावेश पर प्रधानमंत्री के विशेष ध्यान का उल्लेख करते हुये डॉ. जितेन्द्र सिंह ने 'खोले जाने वाले जन धन खातों की संख्या' तथा स्वास्थ्य के हवाले से 'पूरी तरह टीके लगाये हुये बच्चों के प्रतिशत (9-11 माह)' के मद्देनजर वित्तीय समावेश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने के लिये अधिकारियों को प्रयास करने की हिदायत दी।